संख्या-44/2019/1039/71-2-19-24/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
लखनऊ ।

2- **कुलसचिव,**
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

3- **निदेशक,**
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

4- **निदेशक,**
डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।

5- **निदेशक,**
हृदय रोग संस्थान,
कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 27 मई, 2019**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अर्न्तगत राजस्व लेखा के अर्न्तगत असाध्य रोगों के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय को उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 11,00,00,000 लाख (रूपया ग्यारह करोड मात्र) को अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज	धनराशि (लाख में)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	300.00
2	एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।	300.00
3	डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	200.00
4	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	300.00
	योग-	1100.00

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- चिकित्सा शिक्षा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

5- उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु निमयावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019-बी/1-170-दस/2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 द्वारा में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/ महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7- धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2019-बी/1-170-दस/2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 द्वारा द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-44/2019/1039(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संबंधित कोषाधिकारी-लखनऊ, कानपुर।
4. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक)-2/चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1/3/4
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in